

एकमुश्त समझौता योजना

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने कसिनॉं एवं [लघु उद्यमियों](#) के लिये एकमुश्त समझौता योजना (OTS) लागू करने की घोषणा की है।

मुख्य बंदि

- योजना के बारे में:
 - इसका प्रमुख उद्देश्य कसिनॉं और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना और [भूमि विकास बैंकों](#) की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
 - इस योजना के तहत, यद्वित्रीणी 1 जुलाई, 2024 तक अवधपार हो चुके मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के मूलधन की 100 प्रतिशत राशि जमा करते हैं, तो उन्हें **ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी**।
 - इसके अलावा, 5 प्रतिशत अनुदान की सुवधि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पात्र ऋणी सदस्य पुनः ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
 - इस योजना से [भूमि विकास बैंकों](#) से जुड़े **36,351** अवधपार ऋणी सदस्यों को लाभ मल्लेगा।
 - वभिन्निन आपदाओं के कारण कसिनान ऋण की कसितें समय पर नहीं चुका सके, जिससे सहकारी भूमि विकास बैंकों का अवधपार ऋण 760 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
 - इस स्थितिको सुधारने के लिये सरकार **200 करोड़ रुपए** खर्च करेगी, जिससे न केवल ऋणों की वसूली आसान होगी, बल्कि बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा।
- योजना का महत्त्व
 - यह योजना कसिनॉं को **नया ऋण प्राप्त करने और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने** में सहायता करेगी।
 - इस योजना से **छोटे व्यापारियों को वित्तीय राहत** मल्लेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित और सशक्त कर सकेंगे।
 - इस योजना से भूमि विकास बैंकों की **ऋण वसूली दर में सुधार** होगा।

भूमि विकास बैंक के बारे में:

- परिचय
 - भूमि विकास बैंक (Land Development Bank - LDB) विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिये स्थापित [सहकारी बैंक](#) है।
 - ये बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से कसिनॉं को [भूमि सुधार](#), [सर्चिाई](#), [बागवानी](#), कृषि उपकरण खरीदने, [पशुपालन](#) और अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिये दिये जाते हैं।
- इतिहास
 - भारत में पहला भूमि विकास बैंक वर्ष 1920 में पंजाब के इंग में स्थापित किया गया था।
 - इसके बाद वर्ष 1929 में चेन्नई में एक और बैंक की स्थापना हुई, जिसके साथ भूमि विकास बैंकों का वसितार शुरू हुआ।
- वित्त के स्रोत
 - केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुदान और सहायता।
 - कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्तपोषण।
 - दीर्घकालिक वित्त जुटाने हेतु बॉन्ड्स का नरिगम।
 - वभिन्निन सहकारी एवं वाणज्यिक बैंकों से ऋण।
- ऋण वितरण और पुनर्भुगतान
 - भूमि विकास बैंक 20 से 30 वर्षों की अवधि के लिये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
 - ऋण की राशि आमतौर पर भूमि के मूल्य के 50% या वार्षिक [राजस्व](#) के 30 गुना तक होती है।
 - ऋण प्रदान करने से पहले भूमि के स्वामित्व, आय और ऋण आवश्यकता का पूर्ण सत्यापन किया जाता है।
 - **ब्याज दरें आमतौर पर 11-12%** होती हैं, ताकि कसिनान इसे आसानी से चुका सकें।

